

# CACP ने कहा, मवके से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे सरकार

[ त्रिवेणी तिवारी | नई दिल्ली ]

फसलों के मिनिमम सपरीट प्राइस (MSP) पर सुझाव देने वाले कमीशन फौर एप्रीकल्टर कॉस्ट एंड प्राइसेज (CACP) ने सरकार को मवका से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की सलाह दी है। इससे मवका की खेती करने वाले किसानों को अधिक लाभ होगा। CACP के चेयरमैन विजय पॉल शर्मा ने इटी को बताया कि एथेनॉल एक्स्ट्रैक्शन के लिए मवका सबसे अच्छा है। उन्होंने बताया, 'एथेनॉल को मवके से निकालने की प्रक्रिया गन्ने के मुकाबले बेहतर है। फिलहाल एक्स्ट्रैक्शन के लिए गन्ने का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, मवके से एथेनॉल तैयार करने की प्रक्रिया में जो बाई-प्रॉडक्ट बचता है, वह जानवरों के अच्छे

चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे कॉर्न स्टार्च और सिरप भी तैयार किया जा सकता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा।'

**केंद्र सरकार की नेशनल पॉलिसी**  
ऑन बायोफ्यूल्स -  
2018 में 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।

केंद्र सरकार की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स - 2018 में 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 2022 तक 10% पर्सेंट एथेनॉल ब्लेंड करने का टारगेट है। सरकार ने हाल में 'C' हेवी शीरे की कीमत 29 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 43.75 रुपये प्रति लीटर कर दी है। 'B' हेवी शीरे का दाम 1.84 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 54.27 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। सरकार ने पहली बार एथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी और शीरे के इस्तेमाल की अनुमति दी है। कैश की समस्या से जूझ रहीं शुगर मिलों को राहत देने के लिए चीनी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 59.48 रुपये पर तय की गई है। हालांकि, मवका किसानों को ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है।

सरकार की नई नीति में देश में एथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के अलावा अन्य फीडस्टॉक के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इनमें खराब हो चुके अनाज, मवका और अतिरिक्त फूडग्रेन शामिल हैं। कॉर्न से बनने वाले एथेनॉल पर अच्छी कीमत मिलने से किसान अधिक पानी से सीधे जाने वाले धान की जगह मवका उताने को प्रोत्साहित होंगे। इसका फायदा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे पूर्वी राज्यों के किसानों को अधिक मिलेगा, जहां की कमी तेजी से बढ़ रही है। शर्मा ने बताया, 'मवके की कीमतें पिछले दो-तीन सीजन से MSP के नीचे बनी हुई हैं। इसके स्टॉक के निपटारे से जुड़ी मुश्किलों के चलते कमोडिटी की खरीद भी मुद्दा बनी हुई है।'

Economic Times

5-9-2019